



लद्दाख इतिहास के आईने में एक स्वतन्त्रता सेनानी

डॉ. संजीव कुमार गौतम

पूर्व अध्यक्ष-आधुनिक विद्या संकाय

केन्द्रीय बौद्ध विद्या संस्थान (सम विश्वविद्यालय) लेह, केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख: १६४१०४

सारांश-

चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के बीच स्थित संपूर्ण लद्दाख क्षेत्र में अब्दुल सत्तार एक मात्र ऐसे स्वतन्त्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपने अदम्य साहस और निर्भीकता के बल पर दुर्गम पहाड़ियों के बीच स्थित अपने लद्दाख क्षेत्र में आजादी की अखिल मशाल जलाई थी और ब्रिटिश सरकार की जन विरोधी नीति का डटकर सामना किया था तथा अपनी इसी सूझ-बूझ और देश-प्रेम की भावना से ओत-प्रोत (भरपूर) होने के कारण अपने लद्दाख क्षेत्र के अधिकांश लोगों को कमजोर हो चुके डोगरा शासन में ब्रिटिश सरकार की इन जन-विरोधी नीतियों के खिलाफ ला खड़ा कर दिया था और स्वतन्त्रता सेनानी अब्दुल सत्तार ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों की परवाह न करते हुए देश की आजादी के लिए कारगिल स्थित स्कर्दो कारागार में ६ महीना नजरबन्द (कैद) रहे थे तथा इन्होंने इस कारागार में ब्रिटिश सरकार के अमानवीय अत्याचार सह्ये थे और ये अत्याचार इतने क्रूर (कठोर) थे कि ब्रिटिश सरकार ने इनका कारावास के दौरान एक पैर भी काट दिया था। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर से राजधानी दिल्ली में हुई मुलाकात का एक बड़ा सार्थक प्रभाव यह हुआ कि स्वतन्त्रता सेनानी अब्दुल सत्तार में सामाजिक तथा धार्मिक सहष्णुता की भावना और अधिक मजबूत हुई थी और इसी सार्थक प्रभाव के कारण अब्दुल सत्तार ने सम्पूर्ण लद्दाख में बौद्ध-मुस्लिम समुदायों के लोगों के बीच आपसी सामाजिक और धार्मिक सहष्णुता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब्दुल सत्तार के इसी अमन-चैन परस्ती दृष्टिकोण के कारण लद्दाख में गंगा-जमुनी संस्कृति (ब्वउचेपजम बसजतनम) और अधिक मजबूत हुई। स्वतन्त्रता सेनानी स्वतन्त्रता सेनानी अब्दुल सत्तार संपूर्ण लद्दाख क्षेत्र का एकमात्र ऐसा जगमगता सितारा है, जो लद्दाख के सभी लोगों को अपने देश के प्रति हमेशा मर-मिटने की अमिट सीख देता है।

सांकेतिक शब्द -

अविस्मरणीय, उर्दू भाषा, डोगरा शासन, गंगा-जमुनी संस्कृति, दुर्गम पहाड़ों, माठों तथा मर्सलंग, मोरवेन मिशनरी स्कूल, पोली मैदान, स्कर्दो कारागार, के.जी. बकुला, वजीर नरेन्द्र नाथ, डोलमा यंगसे।

CORRESPONDING AUTHOR:	RESEARCH ARTICLE
डॉ. संजीव कुमार गौतम पूर्व अध्यक्ष-आधुनिक विद्या संकाय केन्द्रीय बौद्ध विद्या संस्थान (सम विश्वविद्यालय) लेह, केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख: Email: skgautamcibslh@gmail.com	

प्रस्तावना:

किसी भी देश का समृद्धिशाली इतिहास उसके स्वतन्त्र अस्तित्व पर निर्भर करता है तथा यह स्वतन्त्र अस्तित्व स्वतन्त्रता सेनानियों के समय-समय पर दिये गये बलिदानों से सुरक्षित रह पाता है। इस खोजी लेख के माध्यम से भारत देश के सुदूरवर्ती उत्तर में दुर्गम पहाड़ों के बीच स्थित लद्दाख^१ क्षेत्र के एक ऐसे स्वतन्त्रता सेनानी का विशुद्ध प्राथमिक स्रोतों पर आधारित सटीक इतिहास विवरण पेश है, जो कि लद्दाख^२ क्षेत्र का एकमात्र स्वतन्त्रता सेनानी था और इस स्वतन्त्रता सेनानी द्वारा देश की आजादी के लिए दिये गये अविस्मरणीय योगदान के लिए भारत सरकार से देश के २५^{वें} स्वतन्त्रता दिवस के अवसर (१५ अगस्त १९७२, २४ श्रावण १८९४ शताब्दी) पर सम्मान देने की घोषणा^३ की गयी और फिर २६ जनवरी, १९७३ को इसी सम्मान की जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार द्वारा लेह शहर के पोलो मैदान में लेह-लद्दाख के उप-आयुक्त (Dupty Commissioner) द्वारा प्रदान किया गया था। यह स्वतन्त्रता सेनानी कोई और नहीं, बल्कि दुर्गम पहाड़ों के बीच स्थित इस लद्दाख क्षेत्र के मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार से आने वाला एक जोशीला और निर्भीक नौजवान था और इस नौजवान का नाम अब्दुल सत्तार था।^४

यह वही अब्दुल सत्तार था, जिसने अपने अदम्य साहस तथा लेखनी से लद्दाख जैसे अत्यंत दुर्गम क्षेत्र के लोगों के मन में देश-प्रेम की अटूट भावना का संचार कर दिया था क्योंकि इस अब्दुल सत्तार का लाहोर से प्रकाशित होने वाले ‘इंकलाब’ समाचार पत्र में उर्दू भाषा में एक लेख १९२९ में प्रकाशित हुआ था और इस लेख का मूल भाव “आजादी सबके लिए क्यों जरूरी है।” था। इसी लेख में आगे लिखा गया था कि अपने देश की आजादी से बढ़कर कुछ भी नहीं है और इस आजादी को हमेशा बनाये रखना है।^५

अब्दुल सत्तार के इस लेख से लद्दाख के लोगों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि लद्दाखी लोग डोगरा शासन^६ के अधीन ब्रिटिश शासन के बढ़ते प्रभाव खिलाफ उठ खड़े हुये तथा ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ जगह-जगह आन्दोलन करने लगे और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आन्दोलन का नेतृत्व^६ अब्दुल सत्तार ने स्वयं किया था। लद्दाख जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में अपने शासन की नीतियों के खिलाफ होते विद्रोह को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने विद्रोहियों के खिलाफ धड़ पकड़ तेज कर दी, जिसके कारण अब्दुल सत्तार अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए भूमिगत^७ हो गये परन्तु फिर भी ब्रिटिश सरकार इन विद्रोहियों को पकड़ने के लिए जगह-जगह छापेमारी कर रही थी। ऐसे में आखिरकार जनवरी, १९३८ ई. में अब्दुल सत्तार को लेह शहर से गिरफ्तार^८ करने में सफल रही और फिर इन्हें कारगिल स्थित स्कर्वो कारागार में नजरबंद कर दिया। यहाँ पर अब्दुल सत्तार ६ महीने नजरबंद रखा गया। इस दौरान जोशीले अब्दुल सत्तार का मनोबल तोड़ने के लिए असहनीय यातनाएँ दी गयी थी।

अब्दुल सत्तार की जीवन वृत्त:



स्वतन्त्रता सेनानी
अब्दुल सत्तार
(जन्म: 1887-मृत्यु: 1999)

I. प्रारंभिक परिचय तथा स्वतन्त्रता के लिए कारागार जाना: लद्दाख क्षेत्र के एकमात्र स्वतन्त्रता सेनानी अब्दुल सत्तार की सम्पूर्ण जीवन-वृत्त से संबंधित उपलब्ध सभी प्राथमिक स्रोतों (जिसमें लेखक द्वारा स्वतन्त्रता सेनानी अब्दुल सत्तार के ७६वर्षीय पुत्र रियाज अहमद के साथ तीन बार लिये गये साक्षात्कार भी शामिल हैं) का अत्यंत गंभीरतापूर्ण अध्ययन करने से मालूम होता है कि मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार से आने वाले इस स्वतन्त्रता सेनानी अब्दुल सत्तार का जन्म १८८७ ई. में लेह शहर से १५ कि.मी दूर ‘मझला’ अथवा ‘मर्सलंग’ (Martselang)^९ में हुआ था और इनके पिता का नाम मुहम्मद रमदान^{१०} था, जबकि माता का नाम सलीमा था। उदारवादी विचारों से ओत-प्रोत इस परिवार का मुख्य व्यवसाय खेती करने के साथ-साथ व्यापार करना था। मध्यम वर्गीय इस मुस्लिम परिवार की पैतृक (खानदानी) जमीनें माठों तथा मर्सलंग गाँवों में थी और यहाँ पर इस परिवार का एक पैतृक घर भी था। परिवार के कुछ लोग व्यापार का भी कार्य करते थे। जिसके तहत यह विभिन्न प्रकार का सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने और ले जाने के साथ-साथ क्रय-विक्रय का कार्य करते थे।

अब्दुल सत्तार को बचपन में ही एक संतानहीन मुस्लिम महिला ने गोद⁹⁹ ले लिया था। उपलब्ध साक्ष्यों के अध्ययन से मालूम होता है कि अब्दुल सत्तार का प्रथम प्राथमिक स्कूल “मोरवेन मिशनरी स्कूल”⁹² था। उस समय के लेह-लद्दाख में अंग्रेजी माध्यम का यह एकमात्र प्रथम स्कूल था। इस स्कूल में इनकी प्राथमिक शिक्षा-दीक्षा हुयी थी और इसके बाद की शिक्षा की व्यवस्था घर पर ही हुआ थी। अब्दुल सत्तार पढ़ने में काफी होशियार थे इसलिए शीघ्र ही इन्होंने उर्दू, भोटी, फारसी, अरबी⁹³ के साथ-साथ कश्मीरी भाषा को भी सीख लिया था, यद्यपि उस समय की राजनैतिक परिस्थितियों के कारण अब्दुल सत्तार उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके क्योंकि यह वहीं समय था जब देश की आजादी के लिए स्वतन्त्रता आन्दोलन पूरे देश में फैल चुका था और लद्दाख क्षेत्र भी इस स्वतन्त्रता आन्दोलन में शामिल हो चुका था। ऐसी दशा में देश प्रेमी अब्दुल सत्तार भी इस आन्दोलन से अलग नहीं रह सके क्योंकि अब्दुल सत्तार अपने व्यापार के उद्देश्य से उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों लाहौर, रावलपिण्डी, पेशावर, कश्मीर और दिल्ली जाते रहते थे।⁹⁴ इसका सटीक परिणाम यह हुआ कि नौजवान अब्दुल सत्तार का ध्यान अपने परंपरागत व्यापार की तरफ केंद्रित न होकर देश की आजादी के आन्दोलन की तरफ केन्द्रित हो गया तथा अब अब्दुल सत्तार का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्यवाद विरोधी नीतियों से लद्दाख क्षेत्र के लोगों को अवगत कराना था। यहाँ पर मेरे द्वारा यह उल्लेख करना अति आवश्यक है। इस स्वतन्त्रता सेनानी अब्दुल सत्तार के ७६ वर्षीय बेटे रियाज अहमद ने मेरे साथ दिये गये तीन साक्षात्कार के दौरान स्पष्ट रूप से कहा था कि मेरे पिता (स्वतन्त्रता सेनानी अब्दुल सत्तार) यह बात हमेशा कहते थे कि आजादी सबके लिए आवश्यक है और इस आजादी को हमें प्रत्येक दशा में बनाये रखना है क्योंकि आजादी नहीं, तो कुछ भी नहीं। अतः आजादी हम सबके लिए सर्वोपरि है। स्वतन्त्रता प्रेमी अब्दुल सत्तार अपनी आवाज को लद्दाख क्षेत्र के दूर-दराज तक पहुँचाने के लिए लद्दाख के लोगों के बीच जगह-जगह गुप्त सभाएँ करने लगे तथा इन सभाओं में लोगों को बताते थे कि हमारे देश के लिए ब्रिटिश शासन कितना बुरा है क्योंकि ब्रिटिश शासन की नीतियाँ संपूर्ण लद्दाख क्षेत्र में शोषण का प्रतीक बन चुका था और इसलिए अब्दुल सत्तार ने अपनी देश प्रेमी आवाज को और अधिक बुलंद करने के उद्देश्य से उस समय के एक राष्ट्रीय समाचार पत्र इंकलाब⁹⁵ में एक ओजस्वी लेख लिखा था और इस लेख का प्रकाशन १९३२ ई. में हुआ था। इस लेख को पढ़कर लद्दाखी लोग काफी प्रभावित हुए, यद्यपि अब्दुल सत्तार द्वारा लिखा गया यह लेख ऊर्दू भाषा में था, लेकिन फिर भी इस लेख का संदेश लगभग सभी लोगों ने तक पहुँचा था और इसका सार्थक परिणाम यह हुआ कि लद्दाखी लोगों में देश-प्रेम की भावना को तीव्र संचार हुआ, जिसके कारण ये लोग अब्दुल सत्तार के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन जन विरोधी नीतियों के खिलाफ उठ खड़े हुए तथा जगह-जगह ब्रिटिश शासन की इन नीतियों के खिलाफ संपूर्ण लद्दाख में आन्दोलन करने लगे, जिसके कारण शीघ्र ही संपूर्ण लद्दाख क्षेत्र में आजादी का यह आन्दोलन व्यापक रूप से असफल गया।

अपने शासन के खिलाफ तेज होते इस आजादी के आन्दोलन को ब्रिटिश सरकार ने समाप्त करने की भरकस कोशिश की और इसके तहत ब्रिटिश सरकार ने ऊर्दू भाषा में निकलने वाले ‘इंकलाब’ समाचार के प्रकाशन तथा इसके खरीदने पर पूर्ण प्रतिबन्ध⁹⁶ लगा दिया तथा स्वतन्त्रता के इस आन्दोलन में भाग लेने वाले लोगों की धड़-पकड़ के लिए ब्रिटिश सरकार जगह-जगह छापे-मारी तेज कर दी परन्तु यह आन्दोलन कम होने के बजाय और तेज होता गया क्योंकि लद्दाख क्षेत्र की भौगोलिक संरचना ऐसी है कि स्वतन्त्रता आन्दोलन में सम्मिलित लोगों को पकड़ना ब्रिटिश सरकार के लिए अत्यंत कठिन कार्य था, साथ ही साथ इस भौगोलिक संरचना से परिचित आन्दोलनकारी जिसमें नेतृत्वकर्ता अब्दुल सत्तार भी शामिल थे, भूमिगत हो गये परन्तु ब्रिटिश सरकार भी अपनी हार मानने वाली नहीं थी और इसलिए लद्दाख में कमजोर हो चुके डोगरा शासन के वजीर नरेन्द्र नाथ की सहमति से ब्रिटिश अधिकारियों ने इन आन्दोलनकारियों को पकड़ने के लिए जगह-जगह अपने जासूस नियुक्त कर दिये थे तथा इस प्रकार ब्रिटिश सरकार इन आन्दोलनकारियों को पकड़ने के लिए अत्यंत गंभीर थी और किसी भी कीमत पर लद्दाख में तेज हो चुके स्वतन्त्रता के इस आन्दोलन को समाप्त करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार आन्दोलनकारियों के नेतृत्वकर्ता अब्दुल सत्तार को गिरफ्तार करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल कर लिया था। यहाँ पर विशेष उल्लेखनीय तथ्य यह है कि जब ब्रिटिश सरकार ने अब्दुल सत्तार (स्वतन्त्रता आन्दोलन का नेतृत्वकर्ता) को गिरफ्तार करने का मुख्य उद्देश्य

बना लिया था तभी जम्मू-कश्मीर के वजीर नरेन्द्र नाथ ने ब्रिटिश सरकार से शासन विरोधी गतिविधियों में अब्दुल सत्तार के पूर्ण रूप से शामिल होने की शिकायत की थी क्योंकि वजीर नरेन्द्र नाथ ब्रिटिश शासन के प्रति अत्यंत वफादार था और इसलिए वह नहीं चाहता था कि विषम भौगोलिक स्थिति वाले इस लद्दाख क्षेत्र में ब्रिटिश शासन विरोधी आन्दोलन निरन्तर जारी रहे। ऐसे में स्थिति यह हो गयी कि लद्दाख क्षेत्र के स्वतन्त्रता आन्दोलन के नेतृत्वकर्ता अब्दुल सत्तार अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए पूर्ण रूप से भूमिगत होना पड़ा था और वह देशप्रेमी गतिविधियों का संचालन गुप्त रूप से करने लगे और अपने इस उद्देश्य वह लगभग पाँच साल (१९३३-३८ ई.) तक सफल भी रहे।

आखिरकार काफी लम्बे प्रयास के बाद ब्रिटिश के उप-आयुक्त (Deputy Commissioner) लद्दाख के इस स्वतन्त्रता सेनानी अब्दुल सत्तार को जनवरी, १९३८ ई. में गिरफ्तार करने में सफल हुए तथा इस दौरान अब्दुल सत्तार को हथकड़ी एक डोगरा सिपाही ने लगायी थी। यहाँ से गिरफ्तार करके अब्दुल सत्तार को कारगिल स्थित स्कर्दो कारागार ले जाया गया और यहाँ पर अब्दुल सत्तार को ६ महीना (जनवरी-जुलाई, १९३८ ई.) नजरबन्द रखा गया।^{१७} इस दौरान अब्दुल सत्तार को अमानवीय यातनाएँ दी गयी थी क्योंकि इस लेख से संबंधित प्राप्त समकालीन स्रोतों^{१८} से ज्ञात होता है कि स्कर्दो कारागार की इस नजरबन्दी के दौरान बहादुर और निर्भीक अब्दुल सत्तार का एक पैर भी काट दिया था, जिसके कारण जब यह अब्दुल सत्तार कारागार से छूटे, तब यह लंगड़ा कर चल रहे थे, परन्तु इस सबके बावजूद भी ब्रिटिश सरकार इस बहादुर और निर्भीक स्वतन्त्रता सेनानी अब्दुल सत्तार का मनोबल नहीं तोड़ पायी थी और यही किसी भी सच्चे देश-प्रेमी की अमिट पूंजी (खजाना) होती है। यहाँ पर एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि जब स्वतन्त्रता सेनानी अब्दुल सत्तार को स्कर्दो कारागार से बाहर आने का समाचार लेह (लद्दाख क्षेत्र की राजधानी) के लोगों को मिला, तो ये लोग स्वेच्छा से अपने इस नायक के साथ^{१९} हो गये थे क्योंकि इन ग्रामीण लोगों को ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों ने पहले से ही परेशान कर रखा था और इसका मुख्य कारण यह था कि इन सीधे-सादे ग्रामीण लोगों से ब्रिटिश अधिकारी जबरदस्ती मजदूरी का कार्य कराते थे^{२०} तथा इन अधिकारियों का भू-राजस्व वसूलने का तरीका भी काफी अमानवीय था^{२१} क्योंकि फसल न होने अथवा नष्ट होने पर भी ये ब्रिटिश अधिकारी भू-राजस्व वसूलने में कोई भी रियायत (छूट) नहीं देते थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गयी ६महीने की कठोर कारागार की सजा ने अब्दुल सत्तार को सम्पूर्ण लद्दाख क्षेत्र का एक ऐसा आजादी का नायक बना दिया था कि अब वे (लद्दाखी लोग) अपने नायक अब्दुल सत्तार की बातें और अधिक ध्यान से उत्सुकतापूर्ण सुनते थे क्योंकि ब्रिटिश सरकार अब्दुल सत्तार के मनोबल को बिल्कुल भी नहीं तोड़ पायी थी। इसलिए अब्दुल सत्तार ६महीने की कठोर कारागार नजरबन्दी के बाद सम्पूर्ण लद्दाख क्षेत्र में एक मजबूत, निर्भीक, बहादुर तथा अपने लक्ष्य से न डिगने (हटने) वाले एक लद्दाखी स्वतन्त्रता सेनानी के रूप में पूर्णरूप से स्थापित हो गये। इस प्रकार अब्दुल सत्तार सम्पूर्ण लद्दाख क्षेत्र के एक सर्वमान्य स्वतन्त्रता सेनानी बन गये थे।

II. १९४७ के बाद अब्दुल सत्तार की राजनैतिक गतिविधियाँ: देश के हजारों स्वतन्त्रता सेनानियों के अमिट योगदान के कारण भारत देश १५अगस्त, १९४७ ई. को साम्राज्यवादी ब्रिटिश शासन से पूर्णरूप से स्वतन्त्र हो गया और अब देश प्रख्यात नेताओं का प्रमुख उद्देश्य यह था कि सम्पूर्ण भारत देश के समस्त लोगों के हित में बिना किसी भेद-भाव से एक सुव्यवस्थित शासन प्रणाली स्थापित करना।^{२२} इस समय कांग्रेस पार्टी भारत देश की एकमात्र ऐसी पार्टी थी, जिसकी स्वीकार्यता सम्पूर्ण देश के अधिकतर लोगों में थी इसलिए देश की कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेताओं की ही यह जिम्मेदारी थी कि वह अपने अनुभव व सूझबूझ से देश को उस ऊँचाई (मुकाम) पर ले जायें, जिसका हमारे देश सेकड़ों वर्षों से इंतजार कर रहा था। इसी क्रम में प्रथम कार्य भारतीय संविधान का निर्माण करना था और इस संविधान का निर्माण करने का उत्तरदायित्व बाबा साहेब डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर^{२३} को सौपा गया तथा इस उत्तरदायित्व को बाबा साहेब डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर ने पूर्ण जिम्मेदारी के साथ निभाया, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे देश को एक समता मूलक धर्म निरपेक्ष संविधान^{२४} मिलना संभव हो सका था। अब्दुल सत्तार के ७६वर्षीय बेटे रियाज अहमद ने अपने साक्षात्कार के दौरान बताया कि मेरे पिता (स्वतन्त्रता सेनानी अब्दुल सत्तार) बाबा साहेब

डॉ. अम्बेडकर द्वारा बनाये गये भारतीय संविधान की भूतभूत विशेषताओं से काफी प्रभावित थे और इनका मानना था कि भारत का यह संविधान ही सम्पूर्ण भारत देश की सांस्कृतिक विरासत को अखण्ड बनाये रख सकता है मेरे पिता अब्दुल सत्तार बाबा साहेब डॉ० भीमराव अम्बेडकर से मिलने के लिए १९४७ ई. में नई दिल्ली गये तथा कुछ दिनों बाद इनकी मुलाकात बाबा साहेब डॉ० भीमराव अम्बेडकर से हुई। अपनी इस मुलाकात के संबंध में मेरे पिता बताते हैं कि बाबा साहेब डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने प्रत्येक बात को बड़ी संजीगता के साथ सुना था और इस दौरान इन्होंने कहा था कि आपकी जो समस्या है, उसे लिखित में दे दो, मैं आपकी समस्या का समाधान खोजूंगा। यहाँ पर मेरे पिता अब्दुल सत्तार बिल्कुल स्पष्ट बताते हैं कि बाबा साहेब डॉ० भीमराव अम्बेडकर प्रत्येक व्यक्ति की बात को बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनते थे तथा मुलाकात करने वाले व्यक्ति की मुख्य समस्या के बारे में अवश्य पूछते थे तथा कुछ समस्याओं को वह (बाबा साहेब डॉ० अम्बेडकर) स्वयं भी लिख लेते थे। अपने इस साक्षात्कार के दौरान रियाज अहमद (अब्दुल सत्तार का बेटा) यह भी बताते हैं कि दिल्ली प्रवास के दौरान मेरे पिता की मुलाकात उस समय के प्रमुख कांग्रेसी नेताओं जवाहर लाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम तथा जम्मू-कश्मीर के प्रमुख नेता रहे शेख मुहम्मद अब्दुल्ला से हुयी थी। इस प्रकार मेरे पिता (अब्दुल सत्तार) का दिल्ली जाना और वहाँ पर प्रमुख कांग्रेसी नेताओं के अलावा बाबा साहेब डॉ० भीमराव अम्बेडकर तथा शेख मुहम्मद अब्दुल्ला^{२४} जैसे नेताओं से मिलना एक सार्थक तथा दूरगामी कदम था क्योंकि इस मुलाकात से मेरे पिता अब्दुल सत्तार के मान-सम्मान और राजनैतिक सूझ-बूझ में और अधिक बढ़ोत्तरी हुई तथा अब वह अब्दुल सत्तार अपने इस राजनैतिक सूझ-बूझ का लद्दाख क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए बखूबी उपयोग किया था।

स्वतन्त्र भारत का जम्मू-कश्मीर एक ऐसा राज्य था जिस पर पकिस्तान भी अपना अधिकार मान रहा था, जबकि बैधानिक रूप से जम्मू-कश्मीर राज्य पर भारत का ही अधिकार होना चाहिए था क्योंकि जम्मू-कश्मीर राज्य के राजा महाराजा हरि सिंह थे और हिन्दू होने के नाते महाराजा हरि सिंह अपनी रियासत जम्मू-कश्मीर को भारत में मिलाना चाहते थे तथा इसी उद्देश्य से महाराजा हरि सिंह ने अपनी रियासत जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय के लिए एक विलय पत्र (अधिमिलन पत्र) पर २६ अक्टूबर, १९४७ को हस्ताक्षर किये थे और इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद जम्मू-कश्मीर रियासत का स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त^{२५} हो गया और अब यह राज्य स्वतन्त्र भारत का एक पूर्ण राज्य^{२७} बन गया। शेख मुहम्मद अब्दुल्ला को जम्मू-कश्मीर राज्य का प्रथम प्रधानमंत्री मार्च १९४८ में बनाया गया। जम्मू-कश्मीर राज्य का प्रधानमंत्री बनने के बाद शेख मुहम्मद अब्दुल्ला भारत के प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के साथ ०४ जुलाई, १९४८ को प्रथम बार लद्दाख क्षेत्र की राजधानी लेह आये थे और यह लद्दाख के इतिहास की एक बड़ी राजनैतिक घटना थी क्योंकि भारतीय इतिहास में प्रथम बार देश और राज्य के दो प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू (भारत) तथा शेख मुहम्मद अब्दुल्ला (जम्मू-कश्मीर राज्य के प्रधानमंत्री) का प्रथम बार लेह आगमन हुआ था।

जवाहर लाल नेहरू तथा शेख मुहम्मद अब्दुल्ला का लेह आगमन का मुख्य उद्देश्य यह था कि भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण लद्दाख राज्य^{२८} के बौद्ध तथा मुस्लिम लोगों के सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान देना और यह तभी संभव हो सकता था, जब लद्दाख क्षेत्र के बौद्ध तथा मुस्लिम लोगों के बीच धार्मिक तथा सामाजिक संबंधों को और अधिक मधुर बनाया जाये। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये जम्मू-कश्मीर के प्रधानमंत्री शेख मुहम्मद अब्दुल्ला ने लद्दाख क्षेत्र के एक ऐसे प्रतिनिधि मण्डल को वार्ता के लिए श्रीनगर बुलाने की योजना बनाई, जिसमें दुर्गम पहाड़ियों के बीच स्थित इस लद्दाख क्षेत्र के विभिन्न अंचलों (उप क्षेत्रों) से समझदार लोग शामिल हों क्योंकि लद्दाख क्षेत्र के अलग-अलग अंचलों (उप क्षेत्रों) से आये बुद्धिजीवी लोग ही संबंधित क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को ठीक से समझते थे। लद्दाख क्षेत्र के इस प्रतिनिधि मण्डल में अब्दुल सत्तार को प्रमुख रूप से शामिल किया गया था। अब्दुल सत्तार को इस प्रतिनिधि मण्डल में प्रमुख व्यक्ति के रूप में शामिल किये जाने के पीछे मुख्य कारण यह था कि कारगिल की स्कंदों कारागार में देश की आजादी के लिए ६ महीने की कठोर सजा काटने के कारण

अब्दुल सत्तार समस्त लद्दाख क्षेत्र के लोगों के नायक (Hero) बन चुके थे तथा इसलिए जम्मू-कश्मीर के प्रधानमंत्री शेख मुहम्मद अब्दुल्ला लद्दाख क्षेत्र के नायक अब्दुल सत्तार से वार्ता करने के लिए काफी उत्सुक थे।

सितम्बर, १९४९ को लद्दाख के इस प्रतिनिधि मण्डल की जम्मू-कश्मीर के प्रधानमंत्री शेख मुहम्मद अब्दुल्ला के साथ श्रीनगर में एक बैठक हुई। इस बैठक से संबंधित प्राप्त प्राथमिक साक्ष्यों से मालूम होता है कि इस बैठक में प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व मौलवी मुहम्मद सईद इमाम साहब ने किया था। इस बैठक से संबंधित एक साक्ष्य चित्र^{३६} के अध्ययन से मालूम होता है कि इस वार्ता में शामिल २२ प्रतिनिधियों का एक चित्र लिया गया था, जिसमें १० प्रतिनिधि प्रथम पंक्ति की कुर्सियों पर बैठे हैं जबकि शेष १२ प्रतिनिधि दूसरी पंक्ति (लाइन) में खड़े दिखाई दे रहे हैं। प्रथम पंक्ति में जिन १० प्रतिनिधियों के चित्र दिखायी दे रहे हैं उनके नाम क्रमशः (बायें से दायें) १. अब्दुल सत्तार (लद्दाख का स्वतन्त्रता सेनानी) २. छेतन फुंचोक ३. ख्वाजा गुलाम कादिर कन्दरवल ४. मीर वाइज मुहम्मद सईद ५. मोलवी मुस्ताक ६. शेख मुहम्मद अब्दुल्ला (जम्मू-कश्मीर का प्रधानमंत्री) ७. भिक्षु के.जी. बकुला रिनपोछे ८. आगा मुहम्मद खॉ ९. ख्वाजा गुलाम सुल्तान १०. स्कलजंग रिंगेन (डॉ. दावा)।

लद्दाख क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ जम्मू-कश्मीर के प्रधानमंत्री शेख मुहम्मद अब्दुल्ला के साथ हुई यह प्रथम वार्ता काफी सफल रही क्योंकि इस वार्ता से ही शेख मुहम्मद अब्दुल्ला लद्दाख क्षेत्र की मूलभूत पहेलियों से अवगत हुए थे। साथ ही साथ इस वार्ता के माध्यम से दुर्गम पहाड़ियों के बीच स्थित लद्दाख क्षेत्र की भावी (आगामी) मुद्दे भी तय हुये थे और इस प्रकार आजाद भारत में प्रथम बार लद्दाख क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने का फैसला किया गया था। समय के थपेड़ों (वक्त की मांग) के साथ लद्दाख क्षेत्र के लोगों ने महसूस किया कि यहाँ की विभिन्न समस्याओं के उचित समाधान हेतु लद्दाख क्षेत्र में एक अपना राजनैतिक दल होना ही चाहिए और इस राजनैतिक दल में विभिन्न क्षेत्रों के अलग-अलग समुदायों के बुद्धिजीवी लोग रहें और यह सभी लोग अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं पर प्रमुख सदस्यों के साथ विचार-विमर्श करें। इस राजनैतिक दल के अध्यक्ष पद के लिए अब्दुल सत्तार ने चंगस्पा कलोन सोनम छिवांग^{३०} के नाम का प्रस्ताव किया क्योंकि अब्दुल सत्तार का मानना था कि चंगस्पा कलोन सोनम छिवांग ही लद्दाख के राजनैतिक दल को सफल नेतृत्व दे सकते हैं तथा इसका एक कारण यह था कि चंगस्पा कलोन सोनम छिवांग की विश्वसनीयता लद्दाख की दोनों बौद्ध तथा मुस्लिम समुदायों में काफी थी। ये दोनों समुदायों के लोग भी यहीं चाहते थे। अब्दुल सत्तार के विनम्र अनुरोध तथा यहाँ के दोनों समुदायों के लोगों की भावनाओं देखते हुये चंगस्पा कलोन सोनम छिवांग ने लद्दाख क्षेत्र के इस राजनैतिक दल के अध्यक्ष के लिए अपनी अनुमति तो दे दी^{३१} परन्तु बाद में कुछ कारणों के कारण चंगस्पा कलोन सोनम छिवांग ने इस दल के नेतृत्व करने से इंकार कर दिया और ऐसी दशा में अब्दुल सत्तार तथा अन्य प्रमुख लोगों ने लद्दाख क्षेत्र के इस राजनैतिक दल (मंच) के अध्यक्ष पद के लिए एक बार फिर खोजबीन शुरू कर दी तथा इसके लिए लद्दाख क्षेत्र के दूर-दराज उप क्षेत्रों (अंचलों) में निवास कर रहे दोनों समुदायों के लोगों में साथ विचार-विमर्श का सिलसिला एकबार पुनः प्रारंभ हुआ और फिर एक लम्बे विचार-विमर्श के बाद लद्दाख क्षेत्र के आध्यात्मिक बौद्ध लामा रिनपोछे के.जी. बकुला^{३२} के नाम पर सहमति बनी कि यही लद्दाख क्षेत्र का राजनैतिक नेतृत्व करेंगे, यद्यपि के.जी. बकुला का भारी भरकम व्यक्तित्व होने के कारण लद्दाख के लोगों को इस बात की आशंका थी कि लद्दाख क्षेत्र के बड़े आध्यात्मिक बौद्ध भिक्षु के.जी. बकुला यहाँ का राजनैतिक नेतृत्व क्या स्वीकार करेंगे? और यदि के.जी. बकुला ने लद्दाख का राजनैतिक नेतृत्व स्वीकार करने से मना कर दिया तब क्या होगा? ऐसी दशा में लद्दाख के प्रतिनिधि मण्डल ने फैसला किया कि जम्मू-कश्मीर के प्रधानमंत्री शेख मुहम्मद अब्दुल्ला को इस बात के लिए राजी किया जाये कि वह के.जी. बकुला से लद्दाख का राजनैतिक नेतृत्व स्वीकार करने का अनुरोध करें^{३३} और ऐसा करने से के.जी. बकुला मना नहीं कर पायेंगे, अर्थात् जम्मू-कश्मीर के प्रधानमंत्री शेख मुहम्मद अब्दुल्ला द्वारा अनुरोध करने पर के.जी. बकुला लद्दाख में राजनैतिक नेतृत्व स्वीकार कर लेंगे। अब मूल प्रश्न यह था कि शेख मुहम्मद अब्दुल्ला से यह संदेश कौन पहुँचाएगा कि आप (शेख मुहम्मद अब्दुल्ला) के. जी. बकुला से अनुरोध करें कि वह (के.जी. बकुला) लद्दाख का राजनैतिक नेतृत्व स्वीकार कर लें

और अंततः इस कार्य के लिए अब्दुल सत्तार को ही चुना गया कि वही इस संदेश को जम्मू-कश्मीर के प्रधानमंत्री मुहम्मद शेख अब्दुल्ला तक पहुँचाएँ।³⁴ अब्दुल सत्तार ने उक्त संदेश को शेख मुहम्मद अब्दुल्ला तक पहुँचाया और शेख मुहम्मद अब्दुल्ला पहले से ही के. जी. बकुला के भारी-भरकम व्यक्तित्व से परिचित थे इसलिए शेख मुहम्मद अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को के. जी. बकुला के बारे में अवगत कराया। सारे विवरण से परिचित होने के बाद जवाहर लाल नेहरू तथा शेख मुहम्मद अब्दुल्ला ने के. जी. बकुला से लद्दाख का राजनैतिक नेतृत्व स्वीकार करने का अनुरोध किया। जवाहर लाल नेहरू तथा शेख मुहम्मद अब्दुल्ला का अनुरोध को स्वीकार करने के बाद के. जी. बकुला को लद्दाख क्षेत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व प्रदान किया गया।³⁵ इस प्रकार के.जी. बकुला को लद्दाख क्षेत्र की राजनैतिक कमान सौंपी गयी, जबकि लेह शहर स्थित संकर गोंपा के पास रहने वाली डोल्मा यंगसे (Dolma Yangtse) नामक एक मुखर (होशियार) लद्दाखी महिला को भी राजनैतिक जिम्मेदारी प्रदान की गयी। यह महिला अपनी बुद्धिमत्ता तथा राजनैतिक सूझ-बूझ के कारण कर्पोन अमा डोल्मा प्रथम प्रखर लद्दाखी महिला के रूप में प्रसिद्ध हुई।³⁶ यह महिला संपूर्ण लद्दाख क्षेत्र में उच्च कोटि की प्रखर वक्ता थी। इस महिला की भाषण शैली में इतना आकर्षण होता था कि पुरुष नेता भी इस महिला के सामने खड़े होने (कुछ भी कहने) से डरते थे। डोल्मा यंगसे अर्थात् लद्दाख की प्रथम महिला आमा डोल्मा की इन मूलभूत विशेषताओं के कारण देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू काफ़ी प्रभावित हुये थे और इसी कारण जवाहर लाल नेहरू ने इस अमा डोल्मा को लद्दाख के राजनैतिक क्षेत्र में एक मंच प्रदान किया था। इस प्रकार डोल्मा यंगसे (अमा डोल्मा) लद्दाख क्षेत्र की प्रथम ऐसी महिला नेता थी, जिन्होंने लद्दाख के राजनैतिक क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई थी। उस समय लद्दाख क्षेत्र के दूसरे प्रमुख नेताओं (पुल्कि लामो, चंगस्पा टुण्डुप थांगंग, समा स्पलडन, राकू छोरोल) के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं और यह सभी नेता के.जी. बकुला द्वारा बुलाई गयी प्रत्येक राजनैतिक बैठक में शामिल होते थे। यहाँ विशेष उल्लेखनीय तथ्य यह है कि लद्दाख की आजादी के लिए ६ महीने की सजा काट चुके अब्दुल सत्तार भी राजनैतिक परामर्श के लिए इन बैठकों में हमेशा शामिल रहते थे। के.जी. बकुला के नेतृत्व में लद्दाख के सभी नेताओं ने एकमत से यह प्रस्ताव पास किया कि लद्दाख क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए जम्मू-कश्मीर विधान सभा तथा देश की संसद (लोकसभा तथा राज्यसभा) में प्रतिनिधित्व होना ही चाहिए तथा इसके बाद जम्मू-कश्मीर विधान सभा तथा संसद की लोकसभा तथा राज्यसभा लद्दाख क्षेत्र का प्रतिनिधित्व देने के लिए के.जी. बकुला द्वारा हस्ताक्षरित एक मसौदा (प्रारूप) शेख मुहम्मद अब्दुल्ला तथा जवाहर लाल नेहरू के पास भेजा गया। इस प्रस्ताव का शीघ्र ही सार्थक परिणाम यह हुआ कि लद्दाख क्षेत्र के आध्यात्मिक बौद्ध भिक्षु और विशिष्ट पहचान रखने वाले के.जी. बकुला को जम्मू-कश्मीर विधान सभा तथा देश की संसद में लद्दाख क्षेत्र का प्रतिनिधित्व³⁷ करने का गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ। इसके अलावा के.जी. बकुला लद्दाख क्षेत्र के प्रथम ऐसे राजनेता भी थे, जिन्हें शेख मुहम्मद अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली जम्मू-कश्मीर की मंत्रि मण्डल में कैबिनेट मंत्री १९५१ में बनाया गया था अर्थात् के.जी. बकुला ने शेख मुहम्मद अब्दुल्ला के मंत्रि मण्डल में लद्दाख क्षेत्र के एक मंत्री के रूप में स्थान प्राप्त किया था तथा यहाँ पर लद्दाख की आजादी के नायक अब्दुल सत्तार के योगदान को कदापि नहीं भुलाया जा सकता क्योंकि यह अब्दुल सत्तार ही थे, जिन्होंने लद्दाख क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए के.जी. बकुला के नाम का प्रस्ताव शेख मुहम्मद अब्दुल्ला (जम्मू-कश्मीर के प्रथम व अन्तिम प्रधान मंत्री) के सामने रखा था।³⁸

के.जी. बकुला को जम्मू-कश्मीर मंत्रि मण्डल में एक कैबिनेट मंत्री के रूप में स्थान मिलने के कारण लद्दाख क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को समाधान करना आसान हो गया था क्योंकि के.जी. बकुला की लद्दाख निवासियों में एक विशिष्ट पहचान (आध्यात्मिक एक सामाजिक) पहले से ही थी इसलिए वह लद्दाख क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों (भागों) में स्थित विभिन्न गाँवों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक माह बैठक करते थे तथा यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपनी अथवा अपने गाँव की किसी भी प्रकार की समस्या को के.जी. बकुला के सामने रख सकता था और के.जी. बकुला भी गाँव की समस्याओं को बड़े ही ध्यान से सुनते थे, साथ ही साथ विभिन्न व्यक्तियों द्वारा बतायी गयी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की पूर्ण कोशिश करते थे। के.जी. बकुला के नेतृत्व में संपन्न होने वाली इन बैठकों (सभाओं) में संबंधित क्षेत्र के मुखिया (हल्का सदर) भी शामिल होते थे

तथा अलग-अलग समितियों के प्रमुखों के अलावा इन समितियों के सदस्य भी शामिल होते थे। विशेष अवसरों पर के.जी. बकुला अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए लद्दाख क्षेत्र के दूर-दराज इलाकों (क्षेत्रों) में रह रहे लोगों के लिए सरकारी दर (सस्ती दर) पर चावल व चीनी की आपूर्ति भी सुनिश्चित करते थे। लद्दाख क्षेत्र के विशेष त्यौहारों (लोसर, ईद तथा बुद्ध पूर्णिमा आदि) पर के.जी. बकुला की शक्ति हिदायत होती थी कि बाजारों तथा अन्य दूसरी जगहों पर मिलने वाले वस्तुओं की आपूर्ति में कोई कमी न होने पाये। यहाँ पर उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि के.जी. बकुला बड़े ही लोकतांत्रिक तरीके से विभिन्न सभाओं का आयोजन करते थे और इस दौरान उनकी हमेशा यह कोशिश रहती थी कि उसके सामने रखी गयी समस्याओं का समाधान भी इसी सभा में हो जाये, अर्थात् वह किसी भी समस्या को आगे के लिए नहीं रखते थे। वस्तुतः के. जी. बकुला के नेतृत्व तथा उनकी इस कार्य प्रणाली से सभी लद्दाखी लोग (बौद्ध तथा मुस्लिम लोग) काफी खुश थे।

के.जी. बकुला के सूझ-बूझ भरे राजनैतिक नेतृत्व के कारण जम्मू-कश्मीर सरकार के साथ-साथ भारत सरकार काफी खुश थी क्योंकि लद्दाख क्षेत्र के दो समुदायों (बौद्ध तथा मुस्लिम) के लोगों को के.जी. बकुला के नेतृत्व से कोई शिकायत नहीं थी तथा इसलिए भारत सरकार ने १९६७ ई. में लद्दाख क्षेत्र का प्रथम संसद सदस्य बनाया था।^{३८} अर्थात् के.जी. बकुला को उनकी राजनैतिक सूझ-बूझ के कारण देश की संसद में लद्दाख क्षेत्र का प्रथम प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ था। के.जी. बकुला ने लद्दाख क्षेत्र के एक अत्यंत साधनहीन (गरीब) परिवार से आने वाले सोनम वांग्याल को एम.एल.सी. (MLC) बनने में पूर्ण सहयोग दिया था क्योंकि लद्दाख क्षेत्र में के.जी. बकुला के नेतृत्व में हुये चुनाव में यह (सोनम वांग्याल) दो बार एम.एल.सी (MLC) बना था। वस्तुतः हम कह सकते हैं कि के. जी. बकुला के नेतृत्व में लद्दाख क्षेत्र को स्वतन्त्र भारत के इतिहास में प्रथम बार विशिष्ट राजनैतिक पहचान मिली थी। के.जी. बकुला के कुशल राजनैतिक नेतृत्व को बखूबी समझने वाले अब्दुल सत्तार की दूरदर्शी सोच के कारण ही दुर्गम पहाड़ियों के बीच स्थित इस लद्दाख क्षेत्र को जानने और इसे भारत के शेष राज्यों के साथ जोड़कर इसका विकास करने का प्रथम अवसर जम्मू-कश्मीर सरकार व भारत सरकार से प्राप्त हुआ था।^{३९} लद्दाख के इतिहास में यह एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी। अब्दुल सत्तार ने अपनी बढ़ती आयु (उम्र) के कारण १९७१ में लद्दाख की सक्रिय राजनीति से सन्यास (अलग होना) ले लिया इस प्रकार अब्दुल सत्तार अपने लद्दाख क्षेत्र में लगभग ५० वर्ष तक सक्रिय राजनीति में प्रमुखता के साथ बने रहे और इस दौरान अब्दुल सत्तार ने जहाँ एक तरफ लद्दाख के निवासियों में स्वतन्त्र राजनैतिक अस्तित्व और सामाजिक चेतना का धूम-धूम कर संचार किया तथा देश की आजादी का महत्व भी बखूबी समझाया।

वहीं दूसरी तरफ इन्होंने अपने देश की आजादी के लिए ब्रिटिश सरकार से सीधे लोहा (टक्कर) लिया था तथा इस दौरान अब्दुल सत्तार ने इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं की थी कि यह ब्रिटिश सरकार देश के स्वतन्त्रता सेनानियों के साथ कितना क्रूरतम (निर्दयी) व्यवहार करती है अर्थात् अब्दुल सत्तार ने आजादी का महत्व सबसे पहले खुद समझा और फिर आजादी के इस महत्व को दुर्गम पहाड़ियों की बीच स्थित अपने लद्दाख क्षेत्र के सुदूरवर्ती अंचलों (क्षेत्रों) में निवास कर रहे निवासियों को बड़े ही तार्किक अंदाज में समझाया था। अब्दुल सत्तार के लिए अपनी आजादी सब कुछ थी। यहाँ अब्दुल सत्तार के ७६वर्षीय बेटे रियाज अहमद के कथन का उल्लेख करना अति आवश्यक है क्योंकि मेरे द्वारा लिए गये विभिन्न साक्षात्कारों के दौरान इन्होंने (रियाज अहमद) स्पष्ट कहा था मेरे पिता अब्दुल सत्तार इस कथन को हमेशा दोहराते थे कि हम “सबके लिए आजादी ही सब कुछ है और यदि हमारी आजादी गयी, तो सब कुछ चला गया अर्थात् हम सबकी सच्ची पहचान आजादी से है और यह पहिचान हमारी आजादी से ही अक्षुण्ण रहेगी।” इसलिए मेरे पिता (अब्दुल सत्तार) ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों की परवाह न करते हुए देश की आजादी के लिए कारगिल स्थित स्कर्वो कारागार में ६ महीना नजरबन्द (कैद) रहे थे तथा इन्होंने इस कारागार में ब्रिटिश सरकार के अमानवीय अत्याचार सहे थे और ये अत्याचार इतने क्रूर (कठोर) थे कि ब्रिटिश सरकार ने इनका (अब्दुल सत्तार) कारावास के दौरान एक पैर भी काट दिया था। रियाज अहमद (अब्दुल सत्तार के ७६वर्षीय बेटा) साक्षात्कार के दौरान बड़े ही निराश भाव के साथ मुझे यह भी बताया कि मेरे पिता अब्दुल सत्तार जिस मान-सम्मान के पूर्णतः

हकदार थे वह मान-सम्मान न तो भारत सरकार ने दिया और न ही यह मान-सम्मान जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार ने दिया है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुये रियाज अहमद कहते हैं कि यदि भारत सरकार द्वारा दिया गया स्वतन्त्रता सेनानी के ताम्र पत्र को छोड़ दिया जाये, तो लद्दाख का यह एकमात्र स्वतन्त्रता सेनानी अब्दुल सत्तार का देश की आजादी के लिए किया गया संघर्ष आज भी एक प्रकार से गुमनाम ही है जबकि सामरिक दृष्टिकोण से हमारे इस लद्दाख क्षेत्र का महत्व भारत सरकार के लिए इतना अधिक है कि भारत सरकार लद्दाख क्षेत्र के महत्व को नजरअंदाज चाहकर भी नहीं कर सकती परन्तु इस सबके बावजूद भी केन्द्र तथा राज्य सरकार दोनों ने ही स्वतन्त्रता प्रेमी अब्दुल सत्तार के ब्रिटिश सरकार के साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ किये गये संघर्ष तथा ६ महीने की कठोर कारावास में सजा काटने जैसे योगदान को एक प्रकार से भुला ही दिया है, तभी तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से लद्दाख क्षेत्र काफी बड़ा होने के बावजूद भी यहाँ पर लद्दाख के एकमात्र स्वतन्त्रता सेनानी अब्दुल सत्तार के नाम से न तो कोई संस्था (स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, हवाई अड्डा आदि है और न ही इनके (अब्दुल सत्तार) संबंधित कोई भी लेख लद्दाख के स्कूल, कॉलेज आदि) के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, जबकि हकीकत यही है कि सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण इस लद्दाख क्षेत्र के महत्व को देखते हुये इसको सुरक्षित रखना अति आवश्यक है और यह तभी संभव हो पायेगा, जब केन्द्र तथा राज्य सरकार हमारे लद्दाख क्षेत्र के देश-प्रेमी इतिहास का संरक्षण करें, साथ ही साथ केन्द्र तथा राज्य सरकार लद्दाख राज्य की युवा पीढ़ी को अहसास कराये कि लद्दाख क्षेत्र का इतिहास भी गौरवशाली है, क्योंकि यहाँ पर अब्दुल सत्तार जैसे स्वतन्त्रता सेनानी ने जन्म लिया है^{१०} और वैसे भी अच्छा इतिहास किसी को कभी मरने नहीं देता तथा अपनी संस्कृति को हमेशा संरक्षित करके रखता है और इसी अच्छे इतिहास से हमारी युवा पीढ़ी सीख लेकर अपने देश के लिए मर-मिटने के लिए हमेशा तैयार रहती है तथा अपने राष्ट्र का स्वतन्त्र अस्तित्व बनाये रखती है।

निष्कर्ष:

चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के बीच स्थित संपूर्ण लद्दाख क्षेत्र में अब्दुल सत्तार एक मात्र ऐसे स्वतन्त्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपने अदम्य साहस और निर्भीकता के बल पर दुर्गम पहाड़ियों के बीच स्थित अपने लद्दाख क्षेत्र में आजादी की अखिल मशाल जलाई थी और ब्रिटिश सरकार की जन विरोधी नीति का डटकर सामना किया था तथा अपनी इसी सूझ-बूझ और देश-प्रेम की भावना से ओत-प्रोत (भरपूर) होने के कारण अपने लद्दाख क्षेत्र के अधिकांश लोगों को कमजोर हो चुके डोगरा शासन में ब्रिटिश सरकार की इन जन-विरोधी नीतियों के खिलाफ ला खड़ा कर दिया था क्योंकि अब्दुल सत्तार अपने लोगों के बीच जाकर इस कथन को हमेशा दोहराते थे कि आजादी हम-सबके लिए अमूल्य है और इसे प्रत्येक दशा बनाए रखनी है। आजादी ही हमारे लिए सब कुछ है और यदि हमारी आजादी समाप्त हुई तो मानों कि हमारा सब कुछ समाप्त हो गया। युवावस्था में अब्दुल सत्तार अपनी देश-प्रेम की भावना में इतने ओत-प्रोत थे कि इन्होंने अपनी आजादी तथा ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी नीति से संबंधित १९३२ ई. में एक लेख उर्दू भाषा में लिखा था और इस लेख का प्रकाशन लाहौर से प्रकाशित होने वाले इंकलाब राष्ट्रीय एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया था। अब्दुल सत्तार के इस लेख के लद्दाख के लोगों पर बड़ा सार्थक प्रभाव पड़ा था इस प्रभाव के कारण अधिकतर लद्दाख लोग ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ हो गये थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि अब्दुल सत्तार को ६ महीने कारगिल स्थित स्कदों कारागार में नजरबंद किया गया था और यहाँ पर इन्हें अमानवीय यातनाएँ दी गयी परन्तु फिर भी ब्रिटिश सरकार इस जोशीले स्वतन्त्रता सेनानी के मनोबल को नहीं तोड़ सकी और इसलिए कारागार से बाहर आने के बाद अब्दुल सत्तार संपूर्ण लद्दाख की आजादी के एक लोकप्रिय नायक बन गये थे।

१५अगस्त, १९४७ ई. में देश की आजादी मिलने के बाद लद्दाख क्षेत्र की राजनैतिक तथा सामाजिक मुद्दे (समस्याओं) से संबंधित अब्दुल सत्तार ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू, जम्मू-कश्मीर के प्रधानमंत्री शेख मुहम्मद अब्दुल्ला तथा संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर से मुलाकात की थी और यह मुलाकात काफी सार्थक रही थी, जिसके

कारण लद्दाख क्षेत्र में राजनैतिक, धार्मिक व सामाजिक गतिविधियों का समाधान व्यवस्थित ढंग से सूत्रपात हुआ और इस सुदूरवर्ती लद्दाख क्षेत्र को देश के साथ जुड़ने के एक सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर से राजधानी दिल्ली में हुई मुलाकात का एक बड़ा सार्थक प्रभाव यह हुआ कि स्वतन्त्रता सेनानी अब्दुल सत्तार में सामाजिक तथा धार्मिक सहष्णुता की भावना और अधिक मजबूत हुई थी और इसी सार्थक प्रभाव के कारण स्वतन्त्रता सेनानी अब्दुल सत्तार ने सम्पूर्ण लद्दाख में बौद्ध-मुस्लिम समुदायों के लोगों के बीच आपसी सामाजिक और धार्मिक सहष्णुता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। स्वतन्त्रता सेनानी अब्दुल सत्तार के इसी अमन-चैन परस्ती दृष्टिकोण के कारण लद्दाख में गंगा-जमुनी या मिश्रित संस्कृति (Composite Cultrue) और अधिक मजबूत हुई।

अति संक्षेप में सार यही है कि स्वतन्त्रता सेनानी अब्दुल सत्तार संपूर्ण लद्दाख क्षेत्र का एकमात्र ऐसा जगमगता सितारा है, जो लद्दाख के सभी लोगों को अपने देश के प्रति हमेशा मर-मिटने की अमिट सीख देता है एक सच्चा देश प्रेमी अपने देश के स्वतन्त्र अस्तित्व को कभी भी समाप्त नहीं होने देता इसलिए हम सबको अपने स्वतन्त्रा सेनानियों के देश के दी गयी बलिदानों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए।

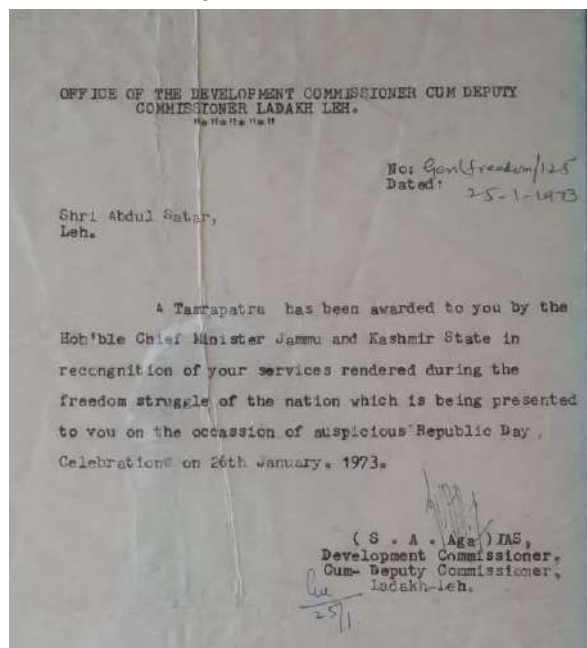
संदर्भ और टिप्पणियाँ :

- 1- लद्दाख भारत के सुदूरवर्ती उत्तर दिशा में स्थित है, जो कि दुर्गम पहाड़ों से घिरा हुआ है तथा इसका अधिकतर भाग बर्फ से ढका रहता है इसलिए यहाँ के लोगों को बर्फीले पर्वतों के लोग कहा गया है। इस लद्दाख के प्राचीन नाम **की-चा (Kie-Chha)** है।
(कनिंघम, अलेक्सजेंडर: लद्दाख-फिजीकल, सटेस्टीकल एण्ड हिस्टोरिकल विद नोटिस ऑफ सराउंडिंग कन्ट्रीज, सागर पब्लिकेशंस वेद मसन, ७२ जनपथ न्यू देहली-१, पब्लिसिड इन इण्डिया, -१९७७ पृष्ठ २,३)
- 2- वही, पृष्ठ १
- 3- भारत सरकार द्वारा लद्दाख के एकमात्र स्वतन्त्रता सेनानी अब्दुल सत्तार को सम्मान स्वरूप प्रदान किया गया ताम्रपत्र-



यहाँ उल्लेखनीय तथ्य यह है कि इस स्वतन्त्रता सेनानी अब्दुल सत्तार का पूरा नाम मुंशी अब्दुल सत्तार था, परन्तु उपलब्ध प्राथमिक दस्तावेजों (आलेखों) में इस स्वतन्त्रता सेनानी का नाम अब्दुल सत्तार ही लिखा मिलता है।

- 4- भारत सरकार द्वारा स्वतन्त्रता सेनानी अब्दुल सत्तार को २५वें स्वतन्त्रता दिवस १५ अगस्त, १९७२ के सुअवसर पर प्रधानमंत्री इंदरा गाँधी द्वारा सम्मान स्वरूप एक प्रशस्ति ताम्रपत्र दिये जाने की घोषणा की गयी थी तथा इस ताम्रपत्र को २६ जनवरी, १९७३ को लेह शहर पोली मैदान में हुये एक समारोह में प्रदान किया गया था -



- 5- <https://rangyul.wordpress.com/2022/06/06munshi-abdul-sattar-the-lone-freedom-fighter-of-ladakh/>
- 6- लद्दाख में डोगरा शासन का प्रारम्भ १८४६ ई. से प्रारंभ होता है, जब लद्दाख के विजेता जोरावर सिंह ने मग्ना थानेदार को लद्दाख में डोगरा शासन का प्रथम प्रशासक (वजीर) नियुक्त किया था। प्रारंभ में यह डोगरा शासन संपूर्ण लद्दाख में काफी शक्तिशाली था, परन्तु समय के थपेड़ों के साथ-साथ डोगरा शासन लद्दाख में कमजोर होता चला गया। जिसके कारण लद्दाख में यह डोगरा शासन केवल प्रतीकात्मक रूप में ही रहा था और ब्रिटिश शासन का जन विरोधी प्रभाव काफी बढ़ गया था। (विकिपीडिया: हिस्ट्री ऑफ लद्दाख)
- 7- <https://rangyul.wordpress.com/2022/06/06munshi-abdul-sattar-the-lone-freedom-fighter-of-ladakh/>
- 8- उस समय लद्दाख के वजीर नरेन्द्र नाथ ने अब्दुल सत्तार की शिकायत की थी कि इसकी गतिविधियाँ ब्रिटिश शासन के खिलाफ काफी तेज हो गयी हैं। अतः अब्दुल सत्तार को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाये।
- 9- अब्दुल सत्तार को जनवरी, १९३८ में डोगरा सिपाही ने गिरफ्तार किया था। (डिपार्टमेन्ट ऑफ इंफार्मेशन एण्ड पब्लिक रिलेशंस, लेह-लद्दाख, ६ जून, २०२१)
- 10- अमेरिका के अब्दुल नासिर खॉ की पुस्तक के अनुसार अब्दुल सत्तार का जन्म होरजेय (श्वद्रमल) में हुआ था। (खॉ, अब्दुल नासिर : मुस्लिम कम्युनिटीज एण्ड कल्चर्स ऑफ, हाउक प्लेस, २०२०, फर्स्ट एडीशन, पृष्ठ २)
- 11- स्वतन्त्रता सेनानी अब्दुल सत्तार के पिता का नाम मुहम्मद रमदान का नाम मुहम्मद रमजान भी मिलता है। (<https://rangyul.wordpress.com/2022/06/06munshi-abdul-sattar-the-lone-freedom-fighter-of-ladakh/>)
- 12- <https://rangyul.wordpress.com/2022/06/06munshi-abdul-sattar-the-lone-freedom-fighter-of-ladakh/>
- 13- वही
- 14- वही
- 15- वही

16- लाहोर से प्रकाशित होने वाला इंकलाब समाचार पत्र एक लोकप्रिय समाचार पत्र था।

17- [जजचेरुध्दतंदहलनसपूवतकवतमेण्ववउध्द२०२२०६६०६उनदीप.इकनसे.जजंत.जीम.सवदम.तिममकवउ.पिहीजमत.वि.संकीध](https://www.youtube.com/watch?v=U2r2d0d6U0c)

18- स्वतन्त्रता सेनानी अब्दुल सत्तार के ७६वर्षीय बेटे रियाज अहमद ने मुझे दिये गये ०३ साक्षात्कारों के दौरान यह स्पष्ट रूप से बताया था कि मेरे पिता तथा स्वतन्त्रता सेनानी अब्दुल सत्तार को स्कट्स कारागार में काफी अमानवीय यातनाए दी गयी थी।

19- स्वतन्त्रता सेनानी अब्दुल सत्तार के ७६वर्षीय बेटे रियाज अहमद ने मुझे दिये गये ०३ साक्षात्कारों के दौरान के चित्र -



20- www.youtube.com/@skgautam7877, <https://rangyul.wordpress.com/2022/06/06munshi-abdul-sattar-the-lone-freedom-fighter-of-ladakh/>

21- <https://rangyul.wordpress.com/2022/06/06munshi-abdul-sattar-the-lone-freedom-fighter-of-ladakh/>

22- वही

अहीर डी.सी.: डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर-राइटिंग्स एण्ड स्पीचेस् (अ रेडी रेफ्रेंस मेनुअल ऑफ १७ वाल्यूम, बी. आर. पब्लिशिंग कार्पोरेशन, अशोक विहार, फेज पट, देहली-११००५२, २००७ पृष्ठ ३११)

23- वही, पृष्ठ ३१७-३१८

24- वही, पृष्ठ ३२०-३२२

25- शेख अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर के एक शक्तिशाली तथा लोकप्रिय नेता थे तथा इनके जवाहर लाल नेहरू से घनिष्ठतम संबंध थे इसलिए यह जम्मू-कश्मीर राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे।

[\(https://rangyul.wordpress.com/2022/06/06munshi-abdul-sattar-the-lone-freedom-fighter-of-ladakh/\)](https://rangyul.wordpress.com/2022/06/06munshi-abdul-sattar-the-lone-freedom-fighter-of-ladakh/)

26- भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड माउण्ट बटेन ने २७अक्टूबर, १९४७ को जम्मू-कश्मीर राज्य के भारत में विलय को अपनी मंजूरी दी थी तथा इसलिए जम्मू-कश्मीर के लोग प्रत्येक वर्ष २६ अक्टूबर को एक भव्य जश्न (समारोह) मनाते हैं।

27- इस जम्मू-कश्मीर राज्य का स्वतन्त्र अस्तित्व भारत सरकार ने ५अगस्त, २०१९ को समाप्त करके जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख नाम के दो केन्द्र शासित राज्य बना दिये हैं। (भारत सरकार का दस्तावेज, अगस्त, २०१९)

28- लद्दाख क्षेत्र भौगोलिक दृष्टिकोण से इसलिए काफी महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि इस लद्दाख क्षेत्र की जहाँ एक तरफ सीमा चीन से मिलती है, तो वहीं दूसरी तरफ इसकी सीमा पकिस्तान से भी मिलती है। अतः लद्दाख क्षेत्र देश के सामरिक (युद्ध) दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

29- यह चित्र जम्मू-कश्मीर की नेशनल कॉफ्रेंस पार्टी (जे. एण्ड के. एन. सी. पार्टी) की बैठक (सितम्बर, १९४९) के दौरान लिया गया चित्र -



प्रथम पंक्ति में जिन १० प्रतिनिधियों के चित्र दिखायी दे रहे हैं उनके नाम क्रमशः (बायें से दायें) १. अब्दुल सत्तार (लद्दाख का स्वतन्त्रता सेनानी) २. छेतन फुंचोक ३. खाजा गुलाम कादिर कन्दरवल ४. मीर वाइज मुहम्मद सईद ५. मोलवी मुस्ताक ६. शेख मुहम्मद अब्दुल्ला (जम्मू-कश्मीर के प्रधानमंत्री) ७. भिक्षु के.जी. बकुला रिन्पोछे ८. आगा मुहम्मद खॉ ९. खाजा गुलाम सुल्तान १०. स्कलजंग रिंछेन (डॉ. दावा)।

30- <https://rangyul.wordpress.com/2022/06/06munshi-abdul-sattar-the-lone-freedom-fighter-of-ladakh/>

31- वहीं

32- आधुनिक लद्दाख के निर्माण में अग्रणी (प्रधान) योगदान देने वाले के.जी. बकुला का पूरा नाम कुशोक ग्यलरस बकुला था। लद्दाख के शाही परिवार से संबंध रखने वाले यह लद्दाख के आध्यात्मिक गुरु, एक राजनेता के साथ-साथ एक बड़े बौद्ध लामा (भिक्षु) थे। इनका जन्म १९ मई, १९१८ तथा मृत्यु ०४ नवम्बर, २००३ को हुई। संपूर्ण लद्दाख क्षेत्र में इन्हें १९ वें कुशोक बकुला रिन्पोछे के रूप में जानते हैं। इन्होंने मंगोलिया देश में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में अपनी सेवाएँ प्रदान की थीं। के.जी. बकुला का प्रमुख योगदान मंगोलिया तथा रूस में बौद्ध धर्म को भारत में तिब्बती निर्वासित समुदाय के साथ जोड़कर पुर्नजीवित करने के अथक प्रयास के रूप विशेष उल्लेखनीय है। के.जी. बकुला का एक अविस्मरणीय योगदान यह भी है कि इन्होंने भारत सरकार द्वारा १९५० में लाये गये उस अध्यादेश का तीव्रतम विरोध किया था, जिसके तहत लद्दाख क्षेत्र के बौद्ध मठों (गोम्पाओं) से संबंधित १२० कनाल भूमि प्रति मठ (गोम्पा) को रखने का प्रावधान था और ऐसे में इस अध्यादेश का पालन करना लद्दाख के बौद्ध अनुयायियों के लिए मृत्यु के दस्तावेज पर स्वयं हस्ताक्षर करने के समान था। के. जी. बकुला के नेतृत्व में लद्दाख निवासियों द्वारा इस अध्यादेश का तीव्र विरोध करने के कारण भारतीय संविधान निर्माता व देश के प्रथम कानून मंत्री बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को यह परामर्श दिया गया कि बौद्ध मठों (गोम्पाओं) से संबंधित इस अध्यादेश को लागू करना लद्दाख जैसे दुर्गम क्षेत्र में रहे हैं। बौद्ध अनुयायियों के खिलाफ सरासर नाइंसाफी होगी और वैसे भी लद्दाख क्षेत्र भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत देश एक अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है, जहाँ पर एक तरफ चीन की सीमा लद्दाख से लगती है तो वही दूसरी तरफ पाकिस्तान की भी सीमा इस लद्दाख क्षेत्र से लगती है। इस प्रकार जवाहर लाल नेहरू ने बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर के उपर्युक्त परामर्श को सही मानते हुए लद्दाख की गोम्पाओं (मठों) से संबंधित इस अध्यादेश को वापिस ले लिया। १९५० के इस अध्यादेश के रद्द होते ही के.जी. बकुला के पद और प्रतिष्ठा में काफी बढोत्तरी हुयी क्योंकि १९५० के इस अध्यादेश के रद्द होना के.जी. बकुला की एक बड़ी जीत के रूप में देखा गया और इस महत्वपूर्ण जीत ने के.जी. बकुला को संपूर्ण लद्दाख क्षेत्र में धार्मिक व राजनैतिक क्षेत्र में एक विशिष्ट पहचान दिलायी थी तथा इस विशिष्ट पहचान के कारण के.जी. बकुला का लद्दाख क्षेत्र के दोनों समुदायों (बौद्ध तथा मुस्लिम) के लोग पहले की तुलना में और अधिक सम्मान करने लगे थे। (विकिपीडिया.ओआर जीधूपचमकपण्वतहए मलहोत्रा गणेश : आधुनिक लद्दाख के वास्तुकार, दैनिक एक्सेलसियर, १४ जनवरी, २०१८/१२ अप्रैल, २०१८)

33- <https://rangyul.wordpress.com/2022/06/06munshi-abdul-sattar-the-lone-freedom-fighter-of-ladakh/>

34- <https://rangyul.wordpress.com/2022/06/munshi-abdul-sattar-the-lone-freedom-fighter-of-ladakh/>

35- वहीं

36- वही

37- स्वतन्त्र भारत के इतिहास में के.जी. बकुला प्रथम ऐसे लद्दाखी थे, जिन्होंने अपने लद्दाख क्षेत्र का जम्मू-कश्मीर की विधान सभा तथा देश की संसद में प्रथम राजनेता के रूप में प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ था।

38- <https://rangyul.wordpress.com/2022/06/06munshi-abdul-sattar-the-lone-freedom-fighter-of-ladakh/>

39- वही

40- लद्दाख के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाके से संबंधित रखने वाले सोनम वांग्यल काफी मेहनती व्यक्ति थे और हर कार्य को बड़ी सूझ-बूझ के साथ करते थे। इसलिए यह के.जी. बकुला के सर्वाधिक विश्वासपात्र बन गये थे जिसके कारण सोनम वांग्यल को के.जी. बकुला का दाहिना हाथ (त्पहीज भंदक) भी कहा जाता था।

41- ०५ अगस्त, २०१६ को केन्द्र की वर्तमान सरकार ने जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा समाप्त करके २ केन्द्र शासित राज्यों में बाँट दिया है और ये २ केन्द्र शासित राज्य जम्मू और कश्मीर राज्य तथा लद्दाख राज्य बिना विधान सभाओं के हैं।

42- लद्दाख के सभी लोगों को अपने देश के प्रति हमेशा मर-मिटने की अमिट सीख देता है।



■ ■ ■